मंगलवार

34 साल से देहरादून का विश्वास

24 मार्च 2026

- देहरादून
- वर्ष 34
- अंक 59
- पृष्ठ 8
- मूल्य ₹ 1.00

दून वैली मेल

सांध्य दैनिक

आर.एन.आई. : 59626/94

email: doonvalley_news@yahoo.com Website: dunvalleymail.com

डीएवीपी से मान्यता प्राप्त

छात्र की हत्या, तीन अरेस्ट

हमारे संवाददाता

देहरादून। कालेज में वर्चस्व को लेकर चल रही आपसी रंजिश के चलते छात्रों के दो गुटो में सघंर्ष हो गया। जिसमें एक छात्र गम्भीर रूप से घायल हो गया। जिसे अस्पताल पहुंचाया गया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गयी। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर तीन छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि अन्य की तलाश जारी है। जानकारी के अनुसार बीती देर रात थाना प्रेमनगर पुलिस को सूचना मिली कि केहरी गांव, प्रेमनगर में कुछ युवकों के बीच हुई आपसी मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे उसके साथियों द्वारा उपचार हेतु प्रेमनगर अस्पताल ले जाया गया है।

सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस मौके पर पहुंची। जहां घायल युवक दिव्यांशु जाटराना पुत्र अमित जाटराना निवासी ग्राम अथाई, थाना भोपा, जिला मुज्जफरनगर, उ.प्र., हाल प्रेमनगर, देहरादून, की गम्भीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों द्वारा उसे दून अस्पताल रेफर किया गया। अस्पताल में एम्बुलेंस खराब होने पर पुलिस द्वारा घायल युवक को पुलिस के सरकारी वाहन से उपचार हेतु दून अस्पताल लाते हुए घायल के परिजनों की घटना की सूचना दी गई, जो सूचना पर दून अस्पताल पहुँचे। दून अस्पताल में घायल युवक की उपचार के दौरान देर रात्रि मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा मृतक के शव को अग्रिम कार्रवाई हेतु मोर्चरी में रखवाया गया। घटना के संबंध में परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने थाना प्रेमनगर में हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गयी। घटना के संबंध में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि दोनों पक्षो के युवक प्रेमनगर स्थित एक निजी शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत है तथा कॉलेज में आपसी वर्चस्व को लेकर उनके मध्य पुरानी रंजिश थी, इसी के चलते बीती रात दोनों पक्षों के मध्य आपस में विवाद व मारपीट की घटना हुई थी। मुकदमें में पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए घटना में शामिल 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। वहीं घटना में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार हुए आरोपियों के नाम युवराज कुमार पुत्र चंद्र प्रकाश, निवासी ग्राम चांदी आरा, थाना चांदी आरा, जिला भोजपुर (बिहार) हाल पता केहरी गांव, लेन नंबर 1, फेस–2, प्रेमनगर देहरादून, मधुर खंडेलवाल पुत्र मोहन खंडेलवाल निवासी गंगापुर रोड रूद्रपुर, कोतवाली रुद्रपुर, उधम सिंह नगर हाल पता चित्रकूट एनक्लेव फेस 2, प्रेमनगर, देहरादून व शिवम शर्मा पुत्र मृत्युंजय कुमार निवासी बिस्वा सरिया नगर गोला रोड दानापुर, थाना दानापुर, पटना, बिहार हाल पता चित्रकूट एनक्लेव फेज 2, थाना प्रेमनगर, देहरादून बताये जा रहे है।

एसटीएफ की वैपन्स तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

भारी मात्रा में आटोमेटिक हथियारों सहित दो गिरफ्तार

2 पम्प एक्शन, 2 पिस्टल, 10 कारतूस व तस्करी में प्रयुक्त कार बरामद

हमारे संवाददाता

उधमसिंहनगर। हथियार तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एसटीएफ एक हिस्ट्रीशीटर सहित दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जिनके पास से 2 पम्प एक्शन, 2 पिस्टल, 10 कारतूस व तस्करी मे प्रयुक्त कार बरामद हुई है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ अजय सिंह द्वारा बताया गया कि पिछले दिनों एसटीएफ द्वारा सभी एसटीएफ टीमो को अवैध रुप से रह रहे विदेशी नागरिको, घुसपैठियों, बंगलादेशी तथा संदिग्ध बाहरी व्यक्तियों, सक्रिय गैंग व अवैध हथियारों के सम्बन्ध में कार्रवाई कर उनकी गिरफ्तारी व धरपकड़ के लिए कार्रवाई के उचित निर्देश दिये गये थे। इस क्रम में उत्तराखण्ड एसटीएफ. की एण्टी नारकोटिक्स टीम कुमाऊं द्वारा कोतवाली जसपुर पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को 2 पम्प एक्शन, 2 पिस्टल, 10 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। जिनके नाम शमशेर सिंह पुत्र कुलवंत सिंह, निवासी ग्राम हजीरा, थाना जसपुर, जनपद उध्सम सिंह नगर व सिमरनजीत पुत्र अजमेर, निवासी अंजनिया फार्म, थाना पुलभट्टा, जनपद उधमसिंह बताये जा रहे है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उक्त वैपन्स शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से लाये थे तथा सम्भवत: जसपुर में बेचने के लिए जा रहे थे। आरोपियों से पूछताछ पर इस प्रकार के वैपन को सम्भवत: फर्जी लाइसेंस बनाकर उनपर चढ़ाकर आगे देना था। वहीं गिरफ्तार हुए बदमाशों मं सिमरनजीत सिहं थाना पुलभट्टा का हिस्ट्रीशीटर बदमाश है जिस पर उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश में एक दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज है।

दून वैली मेल

संपादकीय

बड़ा संकट आने वाला है

इजराइल-ईरान के बीच जारी जंग को अब 24 दिन का समय हो चुका है। भले ही इस जंग में अहम भूमिका निभाने वाले अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे 4 दिन में निपटा देने की बात कही हो लेकिन ईरान की दृढ़ इच्छा और संकल्प शक्ति से 24 दिन बाद भी उसके हौसले बुलंद होने से न सिर्फ मिडल ईस्ट के तमाम देशों को अपनी ताकत का लोहा मानने पर मजबूर कर दिया है बल्कि अमेरिका ट्रंप प्रशासन के भी छक्के छुड़ा दिए हैं। इसने तमाम एशियाई देशों को ही बड़े संकट में नहीं डाल दिया बल्कि अब यूरोपीय देशों तक इसकी धमक सुनाई पड़ने लगी है। ईरान द्वारा मिडल ईस्ट के देशों में अमेरिका द्वारा बनाए गए सैन्य ठिकानों को अपनी मिसाइलों से तबाह किया गया है उससे तो हड़कंप मचा ही हुआ है उसके द्वारा हार्मेज स्टेट से होने वाले तेल, गैस व उर्वरकों के आयात निर्यात पर ताला डाले जाने से इस युद्ध की जद में तमाम विश्व के देश आ गए हैं। इस युद्ध को लेकर लंबे समय से यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी संसद में आए और लोगों को सही हालात की जानकारी दें। पीएम मोदी संसद में आए भी और अपने 23-24 मिनट के भाषण में उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि इस युद्ध का दूरगामी प्रभाव बढ़ने वाला है। उन्होंने साफ कहा कि देश के लोगों को कोरोना काल जैसे संकट का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए तथा जिस तरह से राष्ट्र वासियों ने उस समय एक जुटता और एकता का परिचय दिया था वैसे ही धैर्य संयम का परिचय देने की अपील भी उनके द्वारा की गई। सत्ता में बैठे लोग अब तक इस संकट को संकट मानने को ही तैयार नहीं थे बल्कि इसके उलट संकट को लेकर कुछ भी कहने वालों के खिलाफ कार्यवाही भी की जा रही थी कि वह अफवाह फैला रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह तेल, गैस और उर्वरकों के लिए दूसरे देशों पर इतना ज्यादा निर्भर है कि उसकी 60 फीसदी जरूरतें इनके आयात पर ही निर्भर है जिसमें 80 फीसदी तक की कमी आ सकती है। एनर्जी और उर्वरको का संकट कृषि से लेकर किस-किस क्षेत्र को कितना प्रभावित कर सकता है इसका अंदाजा सूरत के 550 से भी अधिक औद्योगिक इकाइयों के बंद होने से लगाया जा सकता है जहां से कोरोना काल की तरह ही अब मजदूरों का पलायन हो रहा है। आने वाले दिनों में खरीफ की फसल की बुवाई शुरू होनी है अगर खेतों को पानी और उर्वरक नहीं मिलेगा तो क्या होगा, डॉलर के मुकाबले रुपए में हो रही भारी गिरावट से अर्थव्यवस्था पर क्या मार पड़ेगी? देश का शेयर बाजार में जो गिरावट हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है जिसमें निवेशको का लाखों करोड़ रुपया रोज डूब रहा है। गैस और पेट्रोल, डीजल इसके बारे में अभी चिंता न करने की बात की जा रही है आने वाले समय में क्या होने वाला है इसका अनुमान लगा पाना भी मुश्किल है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर यह युद्ध 2-4 सप्ताह भी और लंबा खिंचता है तो तमाम देशों में हाहाकार के हालात पैदा हो जाएंगे। पीएम मोदी को जो कहना था वह उन्होंने कह दिया सवाल समाधान का है जो सरकार के पास भी नहीं है। जो कुछ झेलना है जनता को ही झेलना है। तो एक बार फिर तैयार हो जाइए संकट झेलने के लिए और अपनी बर्बादी का तमाशा देखने के लिए।

उत्तराखंड की प्रतिभा का परचम, वैष्णवी लोहनी बनीं 'मिस टैलेंटेड'

कार्यालय संवाददाता

डोईवाला। सिनमिट कम्युनिकेशंस की ओर से आयोजित फेमिना मिस इंडिया उत्तराखंड-2026 के ग्रैंड फिनाले में वैष्णवी लोहनी ने 'मिस टैलेंटेड' का खिताब अपने नाम कर एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। यह उपलब्धि न केवल उनकी मेहनत और लगन का परिणाम है, बल्कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रतीक है। गौरतलब है कि वैष्णवी इससे पहले मिस उत्तराखंड 2025 में फर्स्ट रनरअप रह चुकी हैं। इसके साथ ही उन्होंने मिस अल्मोड़ा, मिस फोटोजेनिक, मिस ब्यूटीफुल स्माइल और मिस ब्यूटीफुल स्किन जैसे कई प्रतिष्ठित खिताब भी अपने नाम किए हैं, जो उनकी बहुआयामी प्रतिभा को दर्शाते हैं। इस बार के टैलेंट राउंड में वैष्णवी ने प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर के भजन बम लहरी पर योग और नृत्य का अद्भुत संगम प्रस्तुत कर दर्शकों और निर्णायकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी प्रस्तुति में भारतीय संस्कृति की झलक, लय और आध्यात्मिक भाव का अनूठा समावेश देखने को मिला, जिसने सभी को अचंभित

कर दिया। वैष्णवी का कहना है कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं उन्हें न केवल आत्मविश्वास देती हैं, बल्कि अपनी अलग पहचान बनाने का भी अवसर प्रदान करती हैं। उन्होंने कहा कि योग और नृत्य जैसी कलाओं के माध्यम से वह भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहती हैं और लोगों को इसके महत्व से अवगत कराना उनका लक्ष्य है। साईं सृजन पटल परिवार ने वैष्णवी लोहनी को इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनकी यह सफलता युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है और यह दिखाती है कि समर्पण और संस्कार के साथ सफलता अवश्य मिलती है। वहीं, पटल के संस्थापक प्रो.(डॉ.) के. एल. तलवाड़ ने कहा कि वैष्णवी ने अपनी प्रतिभा और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति से पूरे प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने यह भी बताया कि साईं सृजन पटल द्वारा वैष्णवी को सम्मानित किया जाएगा।

एडिफाई वर्ल्ड स्कूल में ग्रेजुएशन डे समारोह संपन्न हुआ

नन्हे मुन्ने बच्चों के डिग्री एवं प्रमाण-पत्र प्राप्त कर चेहरे खिले

देहरादून। एडिफाई वर्ल्ड स्कूल में ग्रेजुएशन डे समारोह अत्यंत भावनात्मक, गरिमामय और यादगार वातावरण में संपन्न हुआ।

आज यहां एडिफाई वर्ल्ड स्कूल में ग्रेजुएशन डे समारोह अत्यंत भावनात्मक, गरिमामय और यादगार वातावरण में संपन्न हुआ। इस समारोह में कक्षा एलकें-3 और कक्षा-पांच छात्रों ने भाग लिया। यह केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि विद्यार्थियों के जीवन की उस महत्वपूर्ण यात्रा का उत्सव था, जिसमें उनके सपनों, संघर्षों और सफलताओं की झलक स्पष्ट दिखाई दे रही थी। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना के साथ हुआ, जिसने वातावरण को पवित्र और प्रेरणादायक बना दिया। विद्यालय के निदेशक महोदय एडवोकेट पंकज होलकर ने अपने प्रेरणादायक संबोधन में उन्होंने विद्यार्थियों को जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहने, असफलताओं से सीख लेने और अपने मूल्यों को सदैव बनाए रखने की सीख

दी। विद्यार्थियों को मंच पर बुलाकर डिग्री एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए, तो उनके चेहरे पर मेहनत का संतोष और सफलता की चमक साफ झलक रही थी। यह पल न केवल विद्यार्थियों के लिए, बल्कि उनके अभिभावकों और शिक्षकों के लिए भी अत्यंत गर्व का था। विद्यार्थियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन और अभिभावकों के समर्थन के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह संस्था उनके जीवन की मजबूत नींव है, जो उन्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति देगी। समारोह के दौरान प्रस्तुत किए गए रंगारंग कार्यक्रमों ने माहौल को और भी जीवंत बना दिया। नृत्य, संगीत ने न केवल मनोरंजन किया, बल्कि विद्यार्थियों की प्रतिभा और आत्मविश्वास को भी उजागर किया। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाध्यापिका हरलीन कौर चौधरी ने अपने संबोधन में विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे अपने संस्थान का नाम रोशन करें और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। यह दिन सभी के हृदय में एक अमिट स्मृति के रूप में सदैव जीवित रहेगा।

पंचम चैत्र नवरात्र पर माँ शक्ति आराधना संध्या महोत्सव का आयोजन

हमारे संवाददाता

देहरादून। ब्रह्मकमल शक्ति संस्था द्वारा इस वर्ष चैत्र नवरात्र एवं हिन्दू नववर्ष के उपलक्ष्य में विभिन्न मंदिरों में "माँ शक्ति आराधना संध्या महोत्सव" कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में पंचम नवरात्र माँ स्कंदमाता के पावन अवसर पर श्रीराम मंदिर, दीपलोक कॉलोनी में "माँ शक्ति आराधना संध्या महोत्सव" का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर संस्था द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रवासियों ने श्रद्धा भाव से सहभागिता की। साथ ही, संस्था द्वारा अंगवस्त्र भेंट कर मातृशक्ति को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धालुओं ने माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप माँ स्कंदमाता की आराधना करते हुए भजन-कीर्तन के माध्यम से अपनी भक्ति प्रकट की। पूरा वातावरण भक्तिमय ऊर्जा और आस्था

से ओत-प्रोत रहा। उपस्थित जनसमूह ने माँ शक्ति से सभी के सुख-समृद्धि एवं कल्याण की कामना की। ब्रह्मकमल शक्ति संस्था के अध्यक्ष अभिनव थापर ने कहा कि नवरात्रि के पांचवें दिन पूजित माँ स्कंदमाता मातृत्व, करुणा एवं संरक्षण का प्रतीक हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमें चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर मातृशक्ति को सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ऐसे धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन समाज में एकता, सकारात्मक ऊर्जा एवं आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति का सनातन को सशक्त बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है, और इसी उद्देश्य से संस्था द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में "माँ शक्ति आराधना संध्या महोत्सव" का आयोजन निरंतर किया जा रहा है। उन्होंने इस अवसर पर मातृशक्ति का आशीर्वाद भी प्राप्त किया।

कार्यक्रम में ब्रह्मकमल शक्ति संस्था के अध्यक्ष अभिनव थापर, क्षेत्रीय पार्षद संगीता गुप्ता, श्रीराम मंदिर समिति के अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता, प्रचार मंत्री सुशील बग्गा, संरक्षक नारायण दास अरोड़ा, चन्द्रप्रभा मनचंदा, सुदेश आहूजा, कोषाध्यक्ष सुनील गोयल, सचिव सुनील शर्मा, सुशीला गुप्ता, विमला अरोड़ा, सरोज कोहली, बीना बग्गा, आशा शर्मा, कोमल जैन, सीमा बांगा, ममता आनंद, सारिका चौधरी, बसंती थापा, सरोज सैनी, सरिता वासन, प्रेरणा गुप्ता, बीना कत्याल, वंदना मग्गो, सरदार जगदीप सिंह चुग, पंडित पुरषोत्तम डिमरी व अन्य गणमान्य व्यक्तियों की विशेष सहभागिता रही। साथ ही संस्था द्वारा मंदिर की कीर्तन मंडलियों एवं आयोजन समिति से जुड़े सदस्यों को सम्मानित भी किया गया।

गांजे के साथ महिला गिरफ्तार

संवाददाता

देहरादून। पुलिस ने गांजे के साथ महिला को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसको न्यायालय में पेश किया जहां से उसको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार नेहरू कालोनी थाना पुलिस ने दूरदर्शन केन्द्र के पास एक महिला को संदिग्ध अवस्था में घुमते हुए देखा तो उसको रूकने का इशारा किया। पुलिस को देख वह भाग खडी हुई। पुलिस ने पीछा कर उसको थोडी दूरी पर ही दबोच लिया। तलाशी लेने पर पुलिस ने उसके कब्जे से 737 ग्राम गांजा बरामद कर लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम सोनी पत्नी ओमप्रकाश निवासी सपेरा बस्ती निकट आकाशवाणी बताया। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसको न्यायालय में पेश किया जहां से उसको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

पश्चिम एशिया में जंग के हालातों पर पीएम मोदी ने लोकसभा में कहा

होमुर्ज का रास्ता रोकना स्वीकार नहीं होगा

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जंग के हालातों पर पीएम मोदी ने पहली बार सार्वजनिक बयान दिया। लोकसभा में उन्होंने कहा कि तनाव खत्म होना चाहिए। बातचीत से ही समस्या का समाधान है। पीएम ने कहा कि नागरिकों और पावर प्लांट पर हमले मंजूर नहीं हैं। होमुर्ज का रास्ता रोकना स्वीकार नहीं होगा। पीएम ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि देश में तेल-गैस संकट न हो। इसके लिए 27 की जगह अब 41 देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं। पश्चिम एशिया में एक करोड़ भारतीय रहते हैं। उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि अभी 3 लाख 75 हजार भारतीय सुरक्षित देश लौट चुके हैं। ईरान से ही हजार भारतीय सुरक्षित लौटे हैं। 700 से ज्यादा मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा हैं।

भारत ने कच्चे तेल के भंडारण को प्राथमिकता दी

पीएम ने कहा- तेल-गैस संकट पररू पिछले एक दशक में भारत ने संकट के समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को प्राथमिकता दी है। आज हमारे पास 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार है। इसे बढ़ाकर 65 लाख मीट्रिक टन से अधिक करने का काम चल रहा है। हमारी तेल कंपनियां अलग स्टोरेज रखती हैं।

हमारे पास पर्याप्त अन्न भंडार

पीएम ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त अन्न भंडार है। आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम हैं। उस वक्त भी ग्लोबल सप्लाई चेन में कमी आई थी। भारत के किसानों को यूरिया की एक बोरी 300 रुपए से भी कम कीमत में दिलाई गई। तेल गैस फर्टिलाइजर से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे, इसके लिए सहयोगियों से संवाद कर रहे हैं।

भारतीयों की सुरक्षा हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता- पीएम ने कहा कि संकट की घड़ी में भारतीयों की सुरक्षा हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता रही है। अभी 3 लाख 75 हजार भारतीय सुरक्षित देश लौट चुके हैं। ईरान से ही हजार भारतीय सुरक्षित लौटे हैं। 700 से ज्यादा मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा हैं।

देश के पावर प्लांट में कोल स्टॉक उपलब्ध- पीएम ने कहा कि युद्ध का एक चौलेंज यह भी है कि देश में गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है। आने वाले समय में बिजली की डिमांड बढ़ती जाएगी। देश के पावर प्लांट में कोल स्टॉक उपलब्ध है। पावर जनरेशन से लेकर सप्लाई तक हर सिस्टम की मॉनीटरिंग की जा रही है।

एनर्जी आज इकोनॉमी की रीढ़

पीएम ने कहा कि हम जानते हैं एनर्जी आज इकोनॉमी की रीढ़ है। ग्लोबल नीड को पूरा करने वाला सोर्स वेस्ट एशिया है। भारत पर इस युद्ध से उत्पन्न दुष्प्रभाव का असर कम हो इसके लिए एक रणनीति से काम कर रहे हैं। भारत सरकार ने एक ग्रुप बनाया है जो हर रोज मिलता है जो आयात-निर्यात में आने वाली दिक्कतों पर निरंतर काम करता है।

मैंने वेस्ट एशिया के प्रमुखों से बात की

पीएम ने कहा कि डिप्लोमेसी में भारत की भूमिका स्पष्ट है। हमने गहरी चिंता व्यक्त की है। मैंने वेस्ट एशिया के प्रमुखों से बात की है। सभी से तनाव कम करने की अपील की है। कॉमर्शियल जहाजों पर हमला और रुकावट अस्वीकार्य है। भारत सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। **एजेंसी**

होर्मुज से जहाजों के आवागमन पर टोल वसूली को ईरान ने किया सिरे से खारिज, कहा- बेबुनियाद अफवाह

नई दिल्ली। ईरान ने उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिनमें कहा जा रहा था कि वह होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों से 2 मिलियन डॉलर (करीब 20 लाख डॉलर) का टोल वसूल रहा है। इस संबंध में भारत में स्थित ईरानी दूतावास ने आधिकारिक बयान जारी कर इन खबरों को बेबुनियाद बताया है।

ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा, कि इस तरह के दावे कुछ व्यक्तियों के निजी विचार हैं और ईरान की आधिकारिक नीति या निर्णय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। दूतावास ने स्पष्ट किया कि ईरान ने कभी भी होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर इस तरह का कोई शुल्क लागू नहीं किया है। यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब हाल के दिनों में अमेरिका और इजराइल के साथ तनाव के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। हालांकि, ईरान ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह महत्वपूर्ण जलमार्ग बंद नहीं है और इसमें नौवहन जारी है। ईरानी विदेश मंत्रालय के अनुसार, युद्ध जैसी परिस्थितियों के बावजूद वह समुद्री यातायात की स्वतंत्रता और सुरक्षा का सम्मान करता है। मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन जलडमरूमध्य को पूरी तरह बंद नहीं किया गया है। इस बीच, होर्मुज से होकर गुजर रहे कुछ जहाजों को विशेष अनुमति के साथ आवाजाही की अनुमति दी जा रही है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, दो भारतीय जहाजकृजग वसंत और पाइन गैसकृभी इस मार्ग से होकर सुरक्षित रूप से गुजर रहे हैं। ये जहाज एलपीजी (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस) ले जा रहे हैं, जो भारत में घरेलू ईंधन के रूप में महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों का मानना है कि होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और यहां किसी भी तरह की बाधा का सीधा असर अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर पड़ सकता है। ऐसे में इस क्षेत्र की स्थिति पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। **एजेंसी**

भारत में ईरानी दूतावास ने दी सफाईय तनाव के बीच भी जारी है सीमित जहाजों की आवाजाही

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक पेश किया है। विधेयक का उद्देश्य सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) अधिनियम, 2008 और कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन करना है। कंपनी अधिनियम निगमन, कॉर्पोरेट प्रशासन, प्रकटीकरण और विघटन को नियंत्रित करता है, जबकि एलएलपी अधिनियम साझेदारों के लिए सीमित देयता के साथ अधिक लचीला ढांचा प्रदान करता है। इस दौरान वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 दो साल के गहन विचार-विमर्श के बाद अब यहां प्रस्तुत किया गया है। कंपनी विधि समिति (सीएलसी) की सिफारिशों और उसकी रिपोर्टों को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया है। सीएलसी में उद्योग मंडलों और पेशेवर संस्थानों के प्रतिनिधि, कानूनी और लेखा विशेषज्ञ शामिल थे। साथ ही बताया कि रिपोर्ट को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए वेबसाइट पर भी रखा गया था, और टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद उनकी जांच की गई। इससे पहले, विधेयक पेश किए जाने से पहले, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी, टीएमसी के सौगत राय और डीएमके की डॉ. टी. सुमति समेत विपक्षी संसादों ने इसका विरोध किया था।

14 किलो के सिलेंडर में 10 किलो घरेलू गैस देने की तैयारी

दाम भी घटेंगे, ईरान युद्ध के चलते तेल कंपनियों का स्टॉक बचाने का प्लान

नई दिल्ली। सरकारी तेल कंपनियां अब घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलो के एलपीजी गैस सिलेंडर में 10 किलो गैस भरकर देने की तैयारी कर रही है। इसका मकसद लिमिटेड स्टॉक को ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक पहुंचाना है। इसके साथ ही सिलेंडर के दाम भी कम किए जा सकते हैं। तेल कंपनियों का मानना है कि 14.2 किलो का सिलेंडर औसतन 35 से 40 दिन चलता है। अगर इसमें सिर्फ10 किलो गैस भरी जाए, तो एक परिवार का काम लगभग एक महीने तक चल जाएगा। इससे जो गैस बचेगी, उसे उन घरों तक पहुंचाया जा सकेगा जहां किल्लत है।

तेल कंपनियों के पास अब ज्यादा रास्ते नहीं बचे हैं, क्योंकि खाड़ी देशों (मिडिल-ईस्ट) से गैस की नई खेप भारत नहीं आ पा रही है। अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग के कारण हालात बिगड़ गए हैं। हाल ही में ईरान ने वहां के एनर्जी प्लांट्स पर मिसाइल हमले किए, जिससे गैस उत्पादन को नुकसान हुआ है। इसके अलावा, होर्मुज रूट भी बंद है, जहां से गैस के जहाज भारत आते हैं। इससे आने वाले दिनों में भारत में एलपीजी की किल्लत और ज्यादा बढ़ सकती है। इसी संकट को देखते हुए तेल कंपनियों ने सिलेंडर में गैस कम करने का फैसला लेने का प्लान बना रही है।

पहचान के लिए स्टिकर लगेगा

अगर यह योजना लागू होती है, तो सिलेंडर की कीमतें भी उसी अनुपात में कम की जाएंगी। अभी दिल्ली में 14.2 किलो के सिलेंडर की कीमत 913 और मुंबई में 912.50 है। 10 किलो गैस मिलने पर ग्राहकों को कम पैसे चुकाने होंगे। पहचान के लिए इन सिलेंडरों पर एक नया स्टिकर लगाया जाएगा, जिस पर गैस की सही मात्रा लिखी होगी। **एजेंसी**

मेहनत से जो कमाया उसे बच्चों में बांट रहा हूं, मैंने राजनीति से कुछ नहीं कमाया

सिद्धू ने कर दिया संपत्ति का बंटवारा, बेटे को पैतृक, बेटी को अमृतसर का घर सौंपा

नई दिल्ली। पंजाब के सीनियर नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी संपत्ति का बंटवारा कर दिया है। उन्होंने अपने जीते जी बेटे और बेटी के नाम पर संपत्ति बांट दी है। उन्होंने फेसबुक पर इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। सिद्धू का कहना है कि उन्होंने अपने पटियाला स्थित पैतृक घर को बेटे करन सिद्धू के नाम किया है। वहीं अमृतसर के अपने खुद के बनाए घर को बेटी राबिया को सौंपा। इस तरह उन्होंने विरासत को समय रहते ही बांटने का फैसला कर लिया। उनके इस फैसले की काफी चर्चा हो रही है और संपत्ति में बेटी को भी बड़ा हिस्सा दिए जाने की तारीफ की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू का पटियाला की यादविंद्र कॉलोनी में बाराबरी गार्डन के पास पुस्तैनी मकान है। वहीं अमृतसर के शानदार घर को उन्होंने अपनी कमाई से तैयार किया था। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि मैंने अपनी पत्नी नवजोत से लंबी चर्चा के बाद यह फैसला लिया कि संपत्ति को बांट दिया जाए। उन्होंने अपने इस फैसले की जानकारी देते हुए परिवार के साथ कुछ तस्वीरें भी साझा की। उन्होंने कहा कि वह ईश्वर में यकीन रखते हैं। अमृतसर की जनता ने मुझे हमेशा सम्मान दिया है और हम उनके साथ हर वक्त खड़े हैं। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मैंने जो मेहनत से कमाया था, उसे बच्चों के बीच बांट रहा हूं। मैंने राजनीति से कुछ भी नहीं कमाया।

उन्होंने फेसबुक पर अपनी डिटेल पोस्ट में लिखा- मैंने माता पार्वती के आशीर्वाद से यह घर बनवाया था, जो मैंने अमृतसर को दिए अपने वचन का सम्मान करने के लिए किया। मेरे बारे में यहां कुछ लोगों ने कहा था कि वह यहां प्रवासी पक्षी की तरह आया हूं और चला जाऊंगा, लेकिन मैंने लोगों को भरोसा दिया था कि मैं आपका बनकर यहीं रहूंगा। सांसद के रूप में मैंने यहीं से दो कार्यकाल पूरे किए थे। इसके बाद भी मैं यहीं बना हुआ हूं। अब भी मेरा वादा जारी है। बता दें नवजोत सिंह सिद्धू को बीते कुछ सालों में लगातार कई झटके झेलने पड़े। एक तरफ गैर-इरादतन हत्या वाले मामले में वह जेल गए थे। फिर वह बाहर निकले तो उनकी पत्नी को कैंसर हो गया था। **एजेंसी**

सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी की कम्पनी से जुड़े बैंक फ्रॉड मामले में जांच को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसियों पर सख्त रुख अपनाया

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशंस से जुड़े बैंक फ्रॉड मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच को अनिच्छुक बताते हुए नाराजगी जाहिर की और दोनों एजेंसियों को आपस में समन्वय बनाकर समयबद्ध तरीके से जांच पूरी करने का निर्देश दिया। सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि अदालत यह तय नहीं कर सकती कि किसे गिरफ्तार किया जाए, लेकिन जांच एजेंसियों की ओर से दिखाई जा रही ढिलाई स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जांच ऐसी होनी चाहिए जो न सिर्फ अदालत बल्कि आम जनता में भी भरोसा पैदा करे। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने साफकहा कि जांच एजेंसियों को आपस में जॉइन हैंड्स करना होगा। साथ ही पीठ ने कहा कि जांच निष्पक्ष, स्वतंत्र और बिना किसी पूर्वाग्रह के होनी चाहिए। अदालत ने सभी संबंधित वित्तीय संस्थानों को ईडी के साथ पूरा सहयोग करने का भी निर्देश दिया और असहयोग की स्थिति में एजेंसी को कोर्ट को सूचित करने की छूट दी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि ईडी अधिकारियों की एक विशेष जांच टीम गठित की गई है और अब तक चार गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि बिना आधार के गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि अब तक करीब 15,000 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं और सच्चाई सामने लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने सामूहिक कन्या पूजन कार्यक्रम में किया प्रतिभाग

1100 कन्याओं का पूजन अत्यंत सौभाग्यपूर्ण:धामी

संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सनातन धर्म मंदिर परिसर में आयोजित सामूहिक कन्या पूजन कार्यक्रम में प्रतिभाग कर 1100 कन्याओं के पूजन को अत्यंत सौभाग्यपूर्ण बताते हुए आयोजन समिति की सराहना की।

आज यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेमनगर, देहरादून स्थित सनातन धर्म मंदिर परिसर में आयोजित सामूहिक कन्या पूजन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को चैत्र नवरात्र की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि चैत्र नवरात्र केवल आस्था का पर्व नहीं, बल्कि श्रद्धा, भक्ति एवं संस्कारों के माध्यम से शक्ति उपासना का महापर्व है। उन्होंने 1100 कन्याओं के पूजन को अत्यंत सौभाग्यपूर्ण बताते हुए आयोजन समिति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में नारी सम्मान को सुदृढ़ करने तथा 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसे मूल्यों को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में कन्या को साक्षात देवी स्वरूप माना गया है। शास्त्रों में भी कन्याओं को अत्यंत सम्मानजनक स्थान दिया गया है। बेटियां अपने संस्कार, स्नेह और त्याग से समाज को सशक्त और समृद्ध बनाती हैं तथा हमारी संस्कृति और परंपराओं की सशक्त वाहक हैं। उन्होंने कहा कि कन्या पूजन के इस

पावन अवसर पर समाज को यह संकल्प लेना चाहिए कि प्रत्येक बेटी को शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान का अधिकार सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा बेटियों की शिक्षा और प्रोत्साहन के लिए छात्रवृत्ति, कक्षा 9 में प्रवेश पर साइकिल वितरण, 12वीं उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन राशि, तथा सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नंदा गौरा योजना, गौरा देवी कन्याधन योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना, पोषाहार योजना सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बेटियों के जन्म से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तक हर स्तर पर उनके सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्र के नौ दिवस केवल पूजा-अर्चना तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आत्मशुद्धि, सेवा, विनम्रता और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को सुदृढ़ करने का अवसर भी प्रदान करते हैं। कन्या पूजन हमारी परंपरा के साथ-साथ सेवा, करुणा और विनम्रता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों से आह्वान किया कि वे हर बेटी की रक्षा, शिक्षा और प्रगति का संकल्प लें, जिससे कन्या पूजन की भावना वास्तविक रूप से सार्थक हो सके। इस अवसर पर विधायक श्रीमती सविता कपूर, भाजपा के महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल, आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहिला, उपाध्यक्ष छावनी परिषद देहरादून विनोद पंवार, भाजपा नेता विनय गोयल एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।

मोटरसाईकिल चोरी

देहरादून। चोरों ने खुले स्थान से मोटरसाईकिल चोरी कर ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार जस्सोवाला निवासी कृष्ण कुमार ने विकासनगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि वह किसी काम से ब्रहमदत्त चौक पर गया था। उसने अपनी मोटरसाईकिल एक स्थान पर खडी की थी। जब वह थोडी देर बाद वापस आया तो उसने देखा कि उसकी मोटरसाईकिल अपने स्थान से गायब थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

चरस के साथ गिरफ्तार

देहरादून। पुलिस ने चरस के साथ एक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसको न्यायालय में पेश किया जहां से उसको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सहसपुर थाना पुलिस ने प्रतीतपुर जाने वाले रास्ते में एक युवक को संदिग्ध अवस्था में घुमते हुए देखा तो उसको रूकने का इशारा किया। पुलिस को देख वह भाग खडा हुआ। पुलिस ने पीछा कर उसको थोडी दूरी पर ही दबोच लिया। तलाशी लेने पर पुलिस ने उसके कब्जे से 155.68 ग्राम चरस बरामद कर ली। पूछताछ में उसने अपना नाम रोजित पुत्र कैलाश नाथ निवासी प्रतीतपुर बताया। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसको न्यायालय में पेश किया जहां से उसको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

विकास के मॉडल पर बिना किसी का नाम लिए जस्टिस भुइयां ने सुनाई खरी-खरी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने कहा कि ज्यूडिशियरी के कुछ हिस्से 'मोर लॉयल देन द किंग सिंड्रोम' से ग्रस्त हो चुकी हैं। यानी ये हिस्से राजा से भी ज्यादा वफादार होने की प्रवृत्ति अपना चुके हैं। इसकारण ही लोग महीनों तक जेलों में सड़ते रहते हैं। जस्टिस भुइयां ने यह बात बेंगलुरु में हुए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पहली नेशनल समिट में कही। 'विकसित भारत में न्यायपालिका की भूमिका' विषय पर जस्टिस भुइयां ने कहा कि कुछ मामलों में सिस्टम इतना ज्यादा सख्त हो रहा है कि जरूरत से ज्यादा केस दर्ज हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस भुइयां ने सरकार और न्यायपालिका के संबंधों,पीएमएलए, यूएपीए कानूनों के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने विरोध प्रदर्शन और सोशल मीडिया गतिविधियों जैसे छोटे मुद्दों पर मनमाने ढंग से क्रिमिनल केस दर्ज करने की निंदा की। जस्टिस भुइयां ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) जैसे कानूनों के तहत आरोपियों को लंबे समय तक हिरासत में रखने पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसतरह के मामलों से निपटने का एक बड़ा साधन है, लेकिन कानून का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल इसके असर को कमजोर करता है। वहीं, यूएपीए को लेकर कहा कि जब दोषसिद्धि की दर लगभग 5 प्रतिशत से भी कम है,तब आरोपी को सालों तक जेल में क्यों रखा जाए। जस्टिस भुइयां ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े कुछ विवादों से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट को एसआईटी बनानी पड़ी हैं, जिससे कोर्ट का सिर्फसमय बर्बाद हुआ। जस्टिस भुइयां ने कहा कि विकसित भारत का विचार राजनीतिक लक्ष्य है और अदालतों को अपने कामकाज में स्वतंत्र रहना चाहिए। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, तब बहस और असहमति के लिए गुंजाइश होनी चाहिए। जबकि असहमति को अपराध नहीं माना जाना चाहिए। जस्टिस भुइयां ने कहा कि भारत में दलितों से भेदभाव जैसी सामाजिक दरारें बर्दाश्त नहीं हो सकतीं। माता-पिता यह जिद नहीं कर सकते कि बच्चे दलित महिला के हाथ का बना खाना नहीं खाएंगे। हम ऐसी स्थिति बर्दाश्त नहीं कर सकते जहां दलित पुरुषों, अनुसूचित जाति के पुरुषों को गलियारों में खड़ा किया जाए और लोग उन पर पेशाब करें। यह विकास का मॉडल नहीं हो सकता।

तमिलनाडु में भाजपा 27 सीटों पर चुनाव लड़ेगी

नई दिल्ली। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सोमवार को सीटों का बंटवारा हो गया है। भाजपा 234 सीटों में से 27 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राज्य में गठबंधन का नेतृत्व करने वाली एआईएडीएमके 178 सीटों परयचुनाव लड़ेगी। वहीं पट्टाली मक्कल काची को 18 और अम्मा मक्कल मुनेत्र कडगम को 11 सीटें मिली हैं। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि चंद्रशेखर के पास कोरमंगला में 49,000 स्क्वॉयर फीट का करीब 200 करोड़ रुपए का बंगला है, जिसकी जानकारी हलफ्नामें में छिपाई है। तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों के लिए सीट शेयरिंग पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, हमारे पारिवारिक रिश्तों को देखते हुए पूरा एनडीए एक परिवार की तरह काम करता है।

फरीदाबाद में पाकिस्तानी जासूस अरेस्ट

फरीदाबाद। हरियाणा के फरीदाबाद में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले गैंग के मेंबर नौशाद अली उर्फलालू को गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नौशाद पेट्रोल पंप पर तीन महीने से पंचर बनाने की दुकान चला रहा था। नौशाद रेलवे स्टेशन, सुरक्षा बलों के फोटो वीडियो बनाता था और उसे व्हाट्सएस ग्रुप्स के जरिए पाकिस्तान भेजने का काम करता था। इसके लिए एक फोटो पर उसे 4 से 6 हजार रुपए मिलते थे। डीसीपी सिटी धवल जायसवाल ने बताया कि अभी तक इसमें गैंग के सरगना मेरठ के सुहेल सहित 22 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने नौशाद के अलावा औरंगाबाद की मीरा को अरेस्ट किया है। एक आरोपी नाबालिग है। तीनों ने बताया कि सुहेल ने ही हमें ग्रुप में जोड़ा था।

सोनम वांगचुक की याचिका खारिज

ह्यनई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. आंगमो की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत वांगचुक की हिरासत के खिलाफदायर याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने देखा कि केंद्र ने 14 मार्च को वांगचुक की हिरासत का अपना आदेश रद्द कर दिया था इसलिए कहा कि इस मामले में अब कुछ भी बाकी नहीं बचा है। इससे पहले कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि क्या सरकार के लिए वांगचुक की सेहत को देखते हुए उनकी हिरासत पर फिर से विचार करने की कोई संभावना है। केंद्र ने 14 मार्च को कहा था कि उसने एनएसए के तहत वांगचुक की हिरासत को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है।

एनकाउंटर कर 3 तस्करों को पकड़ा

बरेली। बरेली में गोवंश के अवशेष मिलने पर एसएसपी ने 2 दरोगा समेत सात पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। पुलिस कप्तान की कार्रवाई से महकमे में हडकंप मच गया। इसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाईयां शुरू हुई। सस्पेंशन के करीब 5 घंटे बाद ही तीन तस्करों को एक एनकाउंटर में गोली मारकर अरेस्ट किया गया। गोली लगने के बाद कंधे पर उठाकर पुलिस वाले ले जाने लगे तो आरोपी बोले- हाय अल्लाहगलती हो गई। सामने आए वीडियो में पीछे से पुलिसवाला कह रहा कि जोर से बोलो। पुलिस के अनुसार, तीनों के पैर में गोली लगी है। हिरासत में लेने के बाद तीनों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस एनकाउंटर में एक सिपाही भी घायल हुआ है। दरअसल, इज्जतनगर के गांव फरीदापुर चौधरी में पिछले 2 दिनों से गोकशी हो रही थी। नाले में करीब 28 बोरियों में बंद गोवंश के अवशेष मिल रहे थे। इसको लेकर माहौल तनावपूर्ण हो गया। हिंदू संगठनों ने एसएसपी से मिलकर विरोध जताया। इसके बाद एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए तीन टीमें बनाई थी।

दिल्ली में महंगी होगी बिजली, अप्रैल से बढ़ेंगे दाम

नई दिल्ली। दिल्लीवासियों के लिए बड़ी खबर है। अप्रैल से बिजली की दरों में बढ़ोतरी की जा सकती है। दावा किया जा रहा है कि ऐसा इसलिए होगा, क्योंकि दिल्ली सरकार तीन बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को 38000 करोड़ रुपये से ज्यादा के बकाया का भुगतान करने की तैयारी कर रही है। एक एजेंसी के मुताबिक सरकार बिजली की दरों में बढ़ोतरी पर सब्सिडी देने की भी योजना बना रही है, ताकि उपभोक्ताओं पर इसका असर कम हो सके। पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को एक निर्देश दिया था। सरकार तीन निजी डिस्कॉम बीआरपीएल, बीवायपीएल और टीपीडीडीएल- को 27200 करोड़ रुपये की कैरिंग कॉस्ट (ब्याज) सहित रेगुलेटरी एसेट्स का भुगतान 7 साल के अंदर करे। रेगुलेटरी एसेट्स वे लागतें हैं जिनकी वसूली भविष्य में होने की उम्मीद होती है। आम आदमी पार्टी के शासन के पिछले एक दशक में बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी न होने के कारण तेजी से बढ़ी हैं। दिल्ली बिजली नियामक आयोग ने जनवरी में केंद्रीय एजेंसी, अपीलीय बिजली न्यायाधिकरण को सूचित किया कि दिल्ली में कुल रेगुलेटरी एसेट्स 38,552 करोड़ रुपये हैं।

यूजीसी लागू करने को लेकर निकाली गई रैली

चतरा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) मोर्चा के द्वारा सोमवार को रैली निकाला गया। रैली मोर्चा के जिला अध्यक्ष देवचरण दांगी के नेतृत्व में निकला। जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल थे।

रैली की शुरुआत मुख्य डाकघर से होकर अव्वल मोहल्ला, गुजरी बाजार, केसरी चौक, जतराहीबाग होते हुए समाहरणालय पहुंचा। जहां लोगों ने यूजीसी लागू करने की मांग को लेकर नारे लगाए। इसके बाद एक शिष्टमंडल ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त को तीन सूत्री मांग पत्र सौपा गया। जिसमें जाति आधारित जनगणना कराने, यूजीसी की इक्रिटी रेगुलेशन बनाने व 2011 के पूर्व नियुक्त सभी शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा डेट से मुक्त करने की मांग की। कार्यक्रम में केदार दागी, नंदकिशोर ठाकुर, राजेश दांगी, भूपेंद्र दांगी, उपेंद्र दांगी रामस्वरूप दांगी, अशोक रजक, अशोक दांगी, राम लखन दांगी, मटुकधारी दांगी, सिकंदर,प्रदीप, प्रसादी, परमेश्वर दांगी ,अशोक भारती, विजय भारती सुरेश ठाकुर पूनम यादव स्वरूप दांगी, नरेश कुमार, समेत काफी संख्या में लोग शामिल थे।

भारत का शिक्षा संकट-रोजगार विहीन डिग्रियां और गाँव से पलायन करते युवा

आज भारत एक शांत लेकिन गहरे मोड़ पर खड़ा है। एक ओर हमारे विश्वविद्यालय हर वर्ष लाखों स्नातक और स्नातकोत्तर तैयार कर रहे हैं, दूसरी ओर इन युवाओं में से बड़ी संख्या में या तो बेरोजगार है, या अपनी योग्यता के अनुरूप काम नहीं पा रहे हैं। इसी समय, हमारे गाँवकृजो कभी आत्मनिर्भर सभ्यता की रीढ़ थेकृधीरे-धीरे अपने युवाओं को खोते जा रहे हैं। यह केवल आर्थिक समस्या नहीं है। यह इस बात की संरचनात्मक विफलता है कि हम शिक्षा, काम और सम्मान को कैसे परिभाषित करते हैं।

दशकों तक हमारी शिक्षा व्यवस्था पर औपनिवेशिक सोच की छाप रही, जिसे उस समय के शासकों की जरूरत के अनुसार आकार मिला। उस समय उद्देश्य स्पष्ट कि ऐसे लोगों की एक श्रेणी तैयार करना जो प्रशासनिक और लिपिकीय कार्य कर सके। भारत ने तब से राजनीतिक और आर्थिक रूप से लंबा सफर तय किया है लेकिन शिक्षा की मूल दिशा अभी भी पूरी तरह नहीं बदली। आज भी हम कौशल के बजाय डिग्रियों, क्षमता के बजाय प्रमाणपत्र, और स्थानीय आजीविका के बजाय शहरी नौकरियों को अधिक महत्व देते हैं। और इसका परिणाम हर जगह दिखाई दे रहा है। युवा सीमित सफेदपोश नौकरियों की तलाश में शहरों की ओर पलायन करते हैं, और अक्सर अस्थिर काम में फंस जाते हैं। वहीं, ग्रामीण भारत एक विरोधाभास का सामना कर रहा हैकृकृषि और पारंपरिक व्यवसायों में रुचि घट रही है, जबकि इन्हीं क्षेत्रों में श्रम की कमी और ठहराव बढ़ रहा है।

दरअसल ऐसा हमेशा नहीं था। भारत के गाँव कभी सशक्त और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्थाएँ थे। कृषि केवल जीविका नहीं, बल्कि पीढ़ियों से विकसित एक विज्ञान थी। बुनाई, बढ़ईगीरी, मिट्टी के बर्तन, धातु कार्य जैसे शिल्प न केवल पहचान बल्कि आय का स्रोत थे। समुदाय आपस में जुड़े हुए थे और आजीविका स्थानीय स्तर पर ही आधारित थी। गुरुकुल की परंपरा, जिसे हम केवल शिक्षा से जोड़ते हैं, वास्तव में एक व्यापक दर्शन थी जहाँ शिक्षा जीवन, प्रकृति और जिम्मेदारी से जुड़ी हुई थी।

दुनिया के अन्य हिस्सों में भी ऐसे ही मॉडल थे, सामुदायिक खेती से लेकर हाथों की कारीगरी तक। ये व्यवस्थाएँ पिछड़ी नहीं थींय बल्कि टिकाऊ, कौशल-आधारित और संतुलित थीं।आज विडंबना यह है कि दुनिया वही चीजें फिर से खोज रही है, जिन्हें हमने पीछे छोड़ दियाकृस्थानीय उत्पादन, पारिस्थितिक संतुलन और कौशल आधारित अर्थव्यवस्था। भारत को आधुनिकता से पीछे नहीं जाना है, बल्कि असंतुलन को सुधारना है। इस समस्या का कोई जादुई समाधान नहीं है। इसके लिए पूरे सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से प्रयास करना होगा। पहला, शिक्षा को केवल साक्षरता नहीं, बल्कि आजीविका से जोड़ना होगा। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों को कृषि विज्ञान, खाद्य प्रसंस्करण, मरम्मत कार्य, डिजिटल साक्षरता और छोटे व्यवसाय प्रबंधन जैसे व्यावहारिक कौशल सिखाने चाहिए। इस दिशा में संकेत देती है, लेकिन इसकी असली परीक्षा गाँवों में प्रभावी क्रियान्वयन में है। दूसरा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को केवल कच्चे उत्पादन तक सीमित नहीं रहना चाहिए। किसानों और स्थानीय उत्पादकों को प्रसंस्करण, पैकेजिंग और सीधे बाजार तक पहुँच में सक्षम बनाना होगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक छोटा ग्रामीण उद्यम भी राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर तक पहुँच सकता है। सिद्धांत सरल हैकृस्थानीय उत्पादन, व्यापक बाजार। तीसरा, ग्रामीण कार्यों को सम्मान देना होगा। एक कुशल किसान, डेयरी संचालक, कारीगर या तकनीशियन कोई विकल्प नहीं, बल्कि राष्ट्र की मजबूती के केंद्र हैं। इनके बिना खाद्य सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला और स्थानीय अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाती है। अंत में, हमें एक असहज सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि हर शिक्षित युवा को पारंपरिक दफ्तर की नौकरी नहीं मिलेगी, और न ही सभी को उसी दिशा में जाना चाहिए। एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था में विविध भूमिकाएँ आवश्यक होती हैं, जिनमें से कई शहरी कॉर्पोरेट ढाँचे से बाहर होती हैं। इसलिए चुनौती केवल बेरोजगारी की नहीं है बल्कि गलत दिशा में बनी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं की है। यदि शिक्षा ऐसे आसान नौकरी के पीछे दौड़ने वाले तैयार करती रहेगी जिनके लिए पर्याप्त नौकरियाँ नहीं हैं, और उन कौशलों की उपेक्षा करती रहेगी जो वास्तविक अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, तो यह अंतर और बढ़ेगा। लेकिन यदि हम शिक्षा को आजीविकाकृविशेषकर ग्रामीण भारतकृसे जोड़ दें, तो यह संकट एक अवसर में बदल सकता है। भारत का भविष्य केवल उसके शहरों, स्टार्टअप्स या कॉर्पोरेट गलियारों में सुरक्षित नहीं होगा। यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि क्या उसके गाँव फिर से सम्मानजनक कार्य, टिकाऊ जीवन और आर्थिक सशक्तता के केंद्र बन पाते हैं। शिक्षा का उद्देश्य बदलना होगा जो ग्रामीण युवाओं को गाँव छोड़ने का साधन नहीं बल्कि गाँव को बदलने की शक्ति प्रदान करे। तभी भारत केवल डिग्रीधारी नहीं, बल्कि एक संतुलित और आत्मनिर्भर राष्ट्र का निर्माण करने वाले नागरिक तैयार कर पाएगा।

ईरान अमेरिका संघर्ष से बाजार में उथल पुथल

पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध तनाव ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दिया है और इसका सबसे बड़ा असर भारत के शेयर बाजार पर देखने को मिला। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते संघर्ष ने निवेशकों के भरोसे को गहरी चोट पहुंचाई है। एक ही कारोबारी दिन में निवेशकों के लगभग बारह लाख करोड़ रुपये डूब गए, जो यह दर्शाता है कि वैश्विक घटनाएं किस तरह घरेलू बाजार को प्रभावित करती हैं। यह गिरावट केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने निवेशकों के मन में डर और अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया।

भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स में करीब पच्चीस सौ अंकों की भारी गिरावट दर्ज की गई और यह गिरकर लगभग चौहत्तर हजार के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी में भी सात सौ से अधिक अंकों की गिरावट आई। यह गिरावट पिछले कई महीनों में सबसे बड़ी मानी जा रही है। बाजार के लगभग सभी क्षेत्रों में बिकवाली का दबाव दिखाई दिया, जिससे यह साफ हो गया कि यह केवल किसी एक सेक्टर की समस्या नहीं बल्कि व्यापक आर्थिक चिंता का परिणाम है।

इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा कारण युद्ध का तेल और गैस क्षेत्रों तक पहुंचना है। खाड़ी क्षेत्र दुनिया के ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख केंद्र है और जब यहां अस्थिरता बढ़ती है तो उसका सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ता है। युद्ध के चलते कई महत्वपूर्ण ऊर्जा ठिकानों पर हमले हुए, जिससे उत्पादन और आपूर्ति दोनों प्रभावित हुए। इसके परिणामस्वरूप कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया और यह एक समय एक सौ पंद्रह डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया। भारत जैसे देश के लिए, जो अपनी जरूरत का अधिकांश तेल आयात करता है, यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर केवल बाजार तक सीमित नहीं रहता बल्कि यह आम लोगों की जिंदगी पर भी असर डालता है। तेल महंगा होने से परिवहन लागत बढ़ती है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती है। यही कारण है कि इस संघर्ष ने महंगाई की आशंका को भी बढ़ा दिया है। इसके अलावा विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली ने बाजार की स्थिति को और कमजोर कर दिया। घरेलू कारणों ने भी इस गिरावट को और गहरा किया। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के प्रमुख शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली, जिससे पूरे बाजार पर दबाव बना। निवेशकों ने जोखिम से बचने के लिए तेजी से अपने निवेश को निकालना शुरू कर दिया, जिससे बाजार में घबराहट और बढ़ गई। मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी लगभग तीन प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई, जो यह दिखाता है कि छोटे निवेशकों पर इसका प्रभाव अधिक पड़ा।

हालांकि इस भारी गिरावट के बाद अगले ही दिन बाजार में कुछ सुधार भी देखने को मिला। निवेशकों ने निचले स्तर पर खरीदारी की, जिससे बाजार में थोड़ी स्थिरता आई। तेल की कीमतों में हल्की गिरावट भी इस सुधार का एक कारण रही। इससे यह संकेत मिलता है कि बाजार में अभी भी उम्मीद बाकी है, लेकिन स्थिति पूरी तरह स्थिर नहीं कही जा सकती। इस पूरे घटनाक्रम का असर केवल शेयर बाजार तक सीमित नहीं रहा बल्कि सोना और चांदी जैसे सुरक्षित निवेश विकल्पों पर भी पड़ा। आमतौर पर संकट के समय इनकी कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन इस बार कीमतों में गिरावट देखने को मिली। इसका कारण यह है कि निवेशकों ने नकदी बनाए रखने के लिए इन धातुओं में भी बिकवाली की। ऊर्जा संकट के चलते पेट्रोल की कीमतों पर भी असर पड़ा है। हालांकि सामान्य पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन यदि कच्चे तेल की कीमतें इसी तरह ऊंची बनी रहती हैं तो भविष्य में आम ईंधन भी महंगा हो सकता है।

विश्व जल दिवस के अवसर पर सहभागिता से समाधान की ओर बढ़ता भारत

विश्व जल दिवस के अवसर पर सहभागिता से समाधान की ओर बढ़ता भारत का एक मनोरम दृश्य नई दिल्ली के विश्व युवक केन्द्र में आयोजित की गई।आज का कार्यक्रम केवल औपचारिकता का निर्वाह नहीं था,बल्कि यह एक ऐसा अवसर बनकर उभरा,जहाँ जल संकट और लैंगिक समानता के प्रश्न को गहराई से समझने,महसूस करने और समाधान की दिशा में सामूहिक संकल्प लेने का प्रयास किया गया। युएनओपीएस द्वारा जल और लैंगिक समानता विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में नीति,प्रशासन,मानवाधिकार और जमीनी अनुभवों का ऐसा संगम देखने को मिला,जिसने इस विमर्श को जीवंत और प्रभावी बना दिया।आज के कार्यक्रम में मुख्य आयोजक विनोद मिश्रा,युएनओपीएस के कान्ट्री मैनेजर,मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. राज भूषण चौधरी केन्द्रीय राज्य मंत्री जल शक्ति मंत्री भारत सरकार तथा विशिष्ट अतिथि भरत लाल की उपस्थिति ने इस आयोजन को गरिमा प्रदान की।आज के मंचीय वक्तव्यों तक सीमित नहीं रही। यह संवाद, सहभागिता और प्रशिक्षण के माध्यम से एक व्यापक सामाजिक संदेश देने में सफल रहा।जल संकट के संदर्भ में जब लैंगिक समानता की बात होती है,तो यह विषय केवल नीतिगत विमर्श नहीं रह जाता, बल्कि यह जीवन की कठोर सच्चाइयों से जुड़ जाता है।अपने उद्बोधन में भरत लाल ने जिस स्पष्टता से इस सच्चाई को सामने रखा,उन्होंने बताया कि देश में लगभग साठ प्रतिशत जल की व्यवस्था महिलाएँ ही करती हैं और इस कार्य में उनका प्रतिदिन लगभग एक घंटा व्यतीत होता है।यह केवल समय का व्यय नहीं,बल्कि उनके जीवन के अवसरों का क्षरण है।उन्होंने अपने प्रशासनिक अनुभवों को साझा करते हुए गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों का उदाहरण दिया,जहाँ जल समितियों का गठन करते समय पचास प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई।इस पहल ने न केवल जल प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाया,बल्कि महिलाओं के भीतर आत्म विश्वास और नेतृत्व की भावना को भी मजबूत किया।उनके अनुभवों से यह स्पष्ट हुआ कि जब महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में स्थान मिलता है,तो योजनाएँ केवल कागजों पर नहीं, बल्कि जमीन पर सफल होती हैं।आज के मुख्य अतिथि डॉ. राज भूषण चौधरी ने अपने संबोधन में सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए कहा कि जल जीवन मिशन जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से देश के हर घर तक सुरक्षित पेयजल पहुँचाने का लक्ष्य केवल विकास का प्रतीक नहीं,बल्कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है।उन्होंने सरकारी आंकड़ों का उल्लेख करते हुए बताया कि देश के करोड़ों परिवारों तक नल से जल पहुँच चुका है और यह प्रक्रिया निरंतर जारी है।उन्होंने कहा किजब घर तक जल पहुँचता है,तो महिलाओं को पानी लाने के श्रम से मुक्ति मिलती है,जिससे उनके जीवन में शिक्षा,स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता के नए द्वार खुलते हैं।उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार जल प्रबंधन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और ग्राम स्तर पर जल समितियों में उनकी भूमिका को सशक्त किया जा रहा है।आज के कार्यक्रम का जीवंत हिस्सा रहा समूह चर्चा,जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिभागियों ने अपने अनुभव,समस्याएँ और समाधान साझा किए।यह चर्चा किसी औपचारिक संवाद की तरह नहीं थी,बल्कि एक खुला मंच था जहाँ जमीनी सच्चाइयाँ सामने आईं।ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े प्रतिनिधियों ने बताया कि किस प्रकार पानी की कमी का सबसे अधिक प्रभाव महिलाओं और बच्चों पर पड़ता है।वहीं कुछ प्रतिभागियों ने यह भी साझा किया कि जहाँ महिलाओं को जल प्रबंधन में शामिल किया गया,वहाँ स्थितियाँ बेहतर हुई हैं।इस समूह चर्चा ने यह स्पष्ट कर दिया कि जल संकट का समाधान केवल सरकारी योजनाओं से नहीं,बल्कि सामुदायिक सहभागिता और सामाजिक चेतना से ही संभव है।यह भी सामने आया कि जब तक समाज के भीतर महिलाओं को बराबरी का स्थान नहीं मिलेगा,तब तक जल प्रबंधन की कोई भी योजना पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकती।कार्यक्रम के दौरान एक और महत्वपूर्ण पहल के रूप में प्रशिक्षण मॉड्यूल पुस्तिका का विमोचन किया गया।यह पुस्तिका केवल एक दस्तावेज नहीं,बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत की गई,जिसमें जल प्रबंधन,स्वच्छता और लैंगिक समानता से जुड़े व्यावहारिक पहलुओं को सरल और प्रभावी ढंग से समझाया गया है।इस पुस्तिका का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं,बल्कि समुदायों को प्रशिक्षित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।इस प्रशिक्षण मॉड्यूल के माध्यम से यह प्रयास किया गया है कि ग्राम स्तर पर कार्य करने वाले लोग, विशेषकर महिलाएँ,जल प्रबंधन के तकनीकी और सामाजिक पहलुओं को समझें और उन्हें व्यवहार में लागू कर सकें।यह पहल इस बात का संकेत है कि अब जल प्रबंधन केवल योजनाओं तक सीमित नहीं है,बल्कि इसे एक जन आंदोलन बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

विनोद मिश्रा ने अतिथि के स्वागत भाषण मेंअपने विचार रखते हुए कहा कि जल और लैंगिक समानता का मुद्दा वैश्विक स्तर पर भी उतना ही महत्वपूर्ण है,जितना स्थानीय स्तर पर। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, सरकार और समुदायों के बीच समन्वय स्थापित कर ही स्थायी समाधान संभव है।कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ते हुए यह स्पष्ट हो गया कि यह आयोजन केवल एक दिन की चर्चा नहीं,बल्कि एक दीर्घकालिक सोच और दिशा का प्रतीक है। हमें यह संदेश देता है कि समाधान कहीं बाहर नहीं,बल्कि हमारे भीतर और हमारे सामूहिक प्रयासों में निहित है।जब संवाद, सहभागिता और संकल्प एक साथ जुड़ते हैं,तभी परिवर्तन की वास्तविक धारा प्रवाहित होती है।

परमाणु छाया में सुलगता पश्चिम एशिया- ईरान-इजरायल-अमेरिका टकराव

वैश्विक स्तरपर पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष अब पारंपरिक सैन्य टकराव की सीमाओं को पार कर एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है,जहां परमाणु ठिकाने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से युद्ध का केंद्र बनते जा रहे हैं।ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ती सैन्य गतिविधियों ने न केवल क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ाया है,बल्कि वैश्विक स्तर पर एक बड़े परमाणु संकट की आशंका भी उत्पन्न कर दी है। हालिया घटनाओं में जिस तरह परमाणु संयंत्रों और अनुसंधान केंद्रों को निशाना बनाया जा रहा है, उसने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या दुनियाँ एक और परमाणु आपदा के मुहाने पर खड़ी है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि युद्ध के 23वें दिन तक आते-आते संघर्ष की प्रकृति में स्पष्ट बदलाव दिखाई देने लगा है।पहले जहां सैन्य ठिकानों,सीमावर्ती क्षेत्रों और रणनीतिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा रहा था, वहीं अब परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले शुरू हो गए हैं। इजरायल द्वारा ईरान के नतांज परमाणु सुविधा पर की गई एयरस्ट्राइक इस दिशा में एक निर्णायक कदम थी। नतांज ईरान के परमाणु कार्यक्रम का केंद्र है, जहां यूरेनियम संवर्धनका कार्य होता है।इसके जवाब में ईरान ने इजरायल के डिमोना परमाणु केंद्र के आसपास मिसाइल हमले किए। यह केंद्र इजरायल की परमाणु क्षमता का सबसे महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। इस प्रकार दोनों पक्षों द्वारा परमाणु ठिकानों को निशाना बनाना केवल सैन्य रणनीति नहीं, बल्कि एक खतरनाक जुआ है, जिसके परिणाम दूरगामी और विनाशकारी हो सकते हैं।रेडिएशन का बढ़ता खतरारू मानवता के लिए अदृश्य दुश्मन है,परमाणु संयंत्रों पर हमले का सबसे बड़ा खतरा केवल विस्फोट नहीं,बल्कि रेडिएशन लीक है।परमाणु संयंत्रों में यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे अत्यधिक रेडियोधर्मी तत्व

मौजूद होते हैं। यदि किसी हमले में इनका रिसाव होता है, तो उसका प्रभाव केवल तत्काल क्षेत्र तकसीमित नहीं रहता, बल्कि हवा, पानी और मिट्टी के माध्यम से हजारों किलोमीटर तक फैल सकता है।रेडिएशन के प्रभाव बेहद गंभीर होते हैं,कैंसर, जन्मजात विकृतियां, प्रतिरक्षा प्रणाली का कमजोर होना और दीर्घकालिक पर्यावरणीय क्षति। चेरनोबिल दुर्घटना और फुक्कुशिमा परमाणु दुर्घटना इसके ज्वलंत उदाहरण हैं, जिनके प्रभाव आज भी महसूस किए जा रहे हैं। यदि पश्चिम एशिया में इसी प्रकार की कोई घटना घटती है, तो उसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर महसूस किया जाएगा। साथियों बात अगर हम अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानें (आईएईए) की भूमिका और ताजा स्थिति को समझने की करें तो इन बढ़ती आशंकाओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। एजेंसी ने हाल ही में डिमोना क्षेत्र में हुए हमले के बाद स्पष्ट किया कि नेगेव परमाणु अनुसंधान केंद्र को किसी प्रकार की क्षति के संकेत नहीं मिले हैं और विकिरण स्तर सामान्य हैं। यह राहत की खबर जरूर है, लेकिन यह स्थिति अस्थायी भी हो सकती है, क्योंकि युद्ध अभी जारी है और किसी भी समय हालात बदल सकते हैं।आईएईए लगातार क्षेत्रीय देशों के साथ संपर्क में है और रेडिएशन स्तर की निगरानी कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल निगरानी पर्याप्त है, या वैश्विक समुदाय को इस संकट को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे? साथियों बात अगर हम डिमोना और नतांजरू क्यों हैं इतने महत्वपूर्ण? इसको समझने की करें तो डिमोना और नतांज केवल दो परमाणु केंद्र नहीं हैं,बल्कि ये दोनों देशों की सामरिक शक्ति के प्रतीक हैं। डिमोना, जिसे दुनिया के सबसे सुरक्षित परमाणु स्थलों में गिना जाता है, इजरायल की कथित परमाणु हथियार क्षमता का आधार है। यहां अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था, जैसे आयरन डोम और एरो मिसाइल सिस्टम तैनात हैं। वहीं नतांज ईरान के परमाणु कार्यक्रम का हृदय है, जहां सैकड़ों सेंट्रीफ्यूज यूरेनियम को समृद्ध करने का कार्य करते हैं। इन दोनों ठिकानों पर हमला केवल सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि विरोधी देश की रणनीतिक क्षमता को कमजोर करने का प्रयास है। साथियों बात अगर हम अमेरिका की भूमिका और बढ़ता दबाव इसको समझने की करें तो इस संघर्ष में अमेरिका की भूमिका भी बेहद अहम है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को दिया गया 48 घंटे का अल्टीमेटम स्थिति को और अधिक गंभीर बना देता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य को नहीं खोलता है, तो अमेरिका ईरान के बिजली संयंत्रों को निशाना बनाएगा। यह चेतावनी केवल सैन्य धमकी नहीं बल्कि आर्थिक और रणनीतिक दबाव का भी हिस्सा है।होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक तेल आपूर्ति का प्रमुख मार्ग है, और इसके बंद होने से विश्व अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। ईरान ने भी जवाब में अमेरिकी और इजरायली ऊर्जा तथा आईटी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की चेतावनी दी है, जिससे साइबर और ऊर्जा युद्ध की संभावना भी बढ़ गई है।यदि यह संघर्ष और बढ़ता है, तो इसका सबसे बड़ा असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ेगा। पश्चिम एशिया दुनिया के तेल और गैस का प्रमुख स्रोत है। होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने या अस्थिर होने से तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है, जिससे वैश्विक महंगाई और आर्थिक मंदी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।भारत जैसे देशों के लिए, जो ऊर्जा आयात पर निर्भर हैं, यह स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है। पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि, औद्योगिक लागत में बढ़ोतरी और आर्थिक विकास दर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

साथियों बात अगर हम युद्ध का मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव को समझने की करें तो परमाणु खतरे के बीच जीना केवल भौतिक संकट नहीं, बल्कि एक गहरा मनोवैज्ञानिक दबाव भी है। युद्धग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले लोग लगातार भय, असुरक्षा और अनिश्चितता के माहौल में जी रहे हैं। बच्चों और युवाओं पर इसका दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे एक पूरी पीढ़ी मानसिक आघात का शिकार हो सकती है।इसके अलावा, यदि रेडिएशन का खतरा वास्तविकता में बदलता है, तो बड़े पैमाने पर विस्थापन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे शरणार्थी संकट और भी गहरा जाएगा। साथियों बात अगर हम क्या यह परमाणु युद्ध की ओर बढ़ता कदम है? इसको समझने की करें तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह संघर्ष परमाणु युद्ध में बदल सकता है? वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि खतरा वास्तविक है। हालांकि अभी तक किसी भी देश ने परमाणु हथियारों के उपयोग का संकेत नहीं दिया है, लेकिन परमाणु ठिकानों पर हमले इस दिशा में एक खतरनाक संकेत हैं।इतिहास गवाह है कि जब युद्ध नियंत्रण से बाहर हो जाता है, तो परिणाम विनाशकारी होते हैं।यदि कूटनीतिक प्रयास विफल होते हैं, तो यह संघर्ष एक ऐसे बिंदु पर पहुंच सकता है, जहां से वापसी संभव नहीं होगी। साथियों बात अगर हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी को समझने की करें तो इस संकट के समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। संयुक्त राष्ट्र,आईएईए और अन्य वैश्विक संस्थाओं को मिलकर युद्धविराम और कूटनीतिक समाधान की दिशा में काम करना होगा।महाशक्तियों को भी यह समझना होगा कि यह केवल क्षेत्रीय संघर्ष नहीं, बल्कि वैश्विक शांति और सुरक्षा का प्रश्न है। यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए, तो इसका परिणाम पूरी मानवता को भुगतना पड़ सकता है। अत: अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी दुनियाँ,पश्चिम एशिया में चल रहा यह संघर्ष अब केवल क्षेत्रीय विवाद नहीं रह गया है, बल्कि यह वैश्विक संकट का रूप ले चुका है।परमाणु ठिकानों पर हमले,रेडिएशन का खतरा, ऊर्जा युद्ध और महाशक्तियों की भागीदारी ये सभी संकेत एक बड़े संकट की ओर इशारा करते हैं।हालांकि अभी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर नहीं हुई है, लेकिन यदि जल्द ही कूटनीतिक समाधान नहीं निकाला गया,तो यह संघर्ष एक ऐसे बिंदु पर पहुंच सकता है, जहां से वापसी असंभव हो जाएगी।दुनियाँ आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां उसे यह तय करना है कि वह शांति और सहयोग का मार्ग अपनाएगी या विनाश और संघर्ष का। यह केवल ईरान, इजरायल या अमेरिका का सवाल नहीं, बल्कि पूरी मानवता के भविष्य का प्रश्न है।

डिजिटल युग में ठगी के बढ़ते जाल से कैसे मिलेगी निजात

देश की राजधानी दिल्ली आज सिर्फ राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र ही नहीं, बल्कि साइबर और वित्तीय अपराधों का भी बड़ा केंद्र दिखाई दे रही है। प्रतिदिन औसतन 50 लाख रुपये की ठगी के मामलों का सामने आना न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि यह कानून-व्यवस्था और डिजिटल सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। यह आंकड़े एक दैनिक अखबार में प्रकाशित किये गए हैं जो चौंकाने वाले दिख रहे हैं। वर्ष 2025 में 184 मामले दर्ज किये गए हैं, लगभग 70,64,80,424 रूपये (30 जून तक) तक ठग लिए गये हैं। इससे पिछले वर्ष 2024 में 1,591 मामले दर्ज हुए और 8,17,64,85,471 रूपये ठग लिए गए। आज ठगी से कैसे बचे ? अभी गैस की क्या कमी हुई ठगों ने इस आपदा को अवसर बना लिया। इस डिजिटल युग में ठगी के बढ़ते जाल से कैसे निजात मिलेगी तो विशेषज्ञों का कहना है कि जागरुकता और सतर्कता सावधानी जरूरी है।

दिल्ली जैसी राजधानी में दिल्ली पुलिस अच्छा कार्य कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में तकनीक के विस्तार के साथ ठगी के तरीके भी बेहद परिष्कृत हो गए हैं। पहले जहां जेबकतरी और साधारण धोखाधड़ी आम थी, वहीं अब ऑनलाइन फ्रॉड, फर्जी कॉल, अपडेट के नाम पर ठगी, और निवेश के झांसे जैसे अपराध तेजी से बढ़े हैं। आम नागरिक, विशेषकर बुजुर्ग और डिजिटल रूप से कम जागरूक लोग, इन ठगों का आसान शिकार बन रहे हैं। दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियां लगातार जागरूकता अभियान चला रही हैं, लेकिन अपराधियों की चतुराई और तकनीकी दक्षता कई बार इन प्रयासों पर भारी पड़ती है। अपराधी अक्सर विदेशी सर्वर, फर्जी सिम कार्ड और डिजिटल वॉलेट्स का इस्तेमाल कर अपनी पहचान छिपा लेते हैं, जिससे जांच और गिरफ्तारी में कठिनाई आती है।

यह स्थिति कई स्तरों पर चिंता पैदा करती है। पहला, आम जनता का डिजिटल लेनदेन पर विश्वास कमजोर होता जा रहा है। दूसरा, देश की आर्थिक सुरक्षा पर इसका असर पड़ता है। तीसरा, कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता और संसाधनों पर भी प्रश्न उठते हैं।

समाधान के लिए बहुस्तरीय रणनीति आवश्यक है। सबसे पहले, साइबर अपराध से निपटने के लिए पुलिस बल को अत्याधुनिक तकनीक और प्रशिक्षण से लैस करना होगा। दूसरे, बैंकों और डिजिटल पेमेंट कंपनियों को अपनी सुरक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाना होगा। तीसरे, स्कूलों और सामाजिक मंचों के माध्यम से डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि लोग ठगी के नए-नए तरीकों से परिचित हो सकें।

इसके अलावा, सरकार को सख्त कानून और त्वरित न्याय व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी, ताकि अपराधियों में डर पैदा हो। साथ ही, आम नागरिकों को भी सतर्क रहना होगाकृअनजान कॉल, लिंक या ऑफर पर भरोसा करने से पहले पूरी जांच करना जरूरी है।

हाल के महीनों में दिल्ली पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफआक्रामक रुख अपनाया। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर संयुक्त आयुक्त रजनीश गुप्ता के नेतृत्व में ऑपरेशन साई-हॉक के तहत दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में बड़े पैमाने पर छापेमारी की गई। इस ऑपरेशन का उद्देश्य उन कॉल सेंटरों और गिरोहों को नेस्तनाबूद करना था जो फर्जी केवाईसी, लॉटरी और निवेश के नाम पर लोगों को लूटते हैं। इस कार्रवाई के बाद साइबर अपराधों की दर में गिरावट दर्ज की गई। अब जांच टीम के विस्तार से इस पकड़ को और मजबूत किया जा सकेगा। यह समझना होगा कि डिजिटल युग में सुरक्षा केवल सरकार या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो यह ठगी का जाल और भी व्यापक रूप ले सकता है, जिससे न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक विश्वास भी प्रभावित होगा। डिजिटल युग ने जहां हमारी जिंदगी को आसान बनाया है, वहीं ठगों के लिए नए रास्ते भी खोल दिए हैं। आज मोबाइल, इंटरनेट और ऑनलाइन बैंकिंग के बढ़ते उपयोग के साथ डिजिटल ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।

हर दिन आम लोग अपनी मेहनत की कमाई साइबर अपराधियों के जाल में फंसा रहे हैं। ऐसे में यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि डिजिटल ठगी से कैसे बचा जाए और इस समस्या पर प्रभावी नियंत्रण कैसे हो। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि डिजिटल ठगी केवल तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि जागरूकता की कमी का परिणाम भी है। ठग अक्सर फर्जी कॉल, मैसेज, ईमेल या लिंक के माध्यम से लोगों को भ्रमित करते हैं। आपका बैंक खाता बंद हो जाएगा, केवाईसी अपडेट करें, लॉटरी लगी है कृजैसे लालच और डर पैदा करने वाले संदेश लोगों को जल्दी फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं। इसी जल्दबाजी का फायदा अपराधी उठाते हैं।इस समस्या से निजात पाने का पहला और सबसे प्रभावी उपाय हैकृजागरूकता। आम नागरिकों को यह समझना होगा कि कोई भी बैंक या सरकारी संस्था कभी भी फोन या मैसेज के जरिए पासवर्ड या नहीं मांगती। ऐसे किसी भी अनुरोध को तुरंत नजरअंदाज करना चाहिए। साथ ही, अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचना और केवल आधिकारिक वेबसाइट या ऐप का ही उपयोग करना जरूरी है।

दूसरा महत्वपूर्ण पहलू हैकृतकनीकी सुरक्षा। मोबाइल और कंप्यूटर में अपडेटेड एंटीवायरस रखना, मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करना और समय-समय पर पासवर्ड बदलना जरूरी है। दो-स्तरीय सुरक्षा का उपयोग भी ठगी के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकता है।तीसरा, सरकार और संस्थाओं की भूमिका भी बेहद अहम है।

साइबर अपराधों पर सख्त कानून, त्वरित कार्रवाई और पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिलना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सौगात

11.59 करोड़ से बनेगा शारदा तटबंद, चिलियाघोल व 28 हेक्टेयर भूमि सुरक्षित

संवाददाता

चम्पावत। बाढ़ सुरक्षा हेतु तटबंध निर्माण के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुल 1159.43 लाख (11.59 करोड़) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

आज यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जनपद चम्पावत में आपदा प्रबंधन एवं जनसुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अंतर्गत टनकपुर में शारदा नदी के दाएं तट पर बाढ़ सुरक्षा हेतु तटबंध निर्माण के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुल 1159.43 लाख (11.59 करोड़) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

यह तटबंध बूम से टनकपुर के मध्य शारदा नदी के किनारे स्थित लगभग 28 हेक्टेयर उपजाऊ कृषि भूमि एवं चिलियाघोल क्षेत्र को बाढ़ और भू-कटाव से सुरक्षित करेगा। परियोजना को राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अंतर्गत स्वीकृत किया गया है, जिससे संवेदनशील क्षेत्रों में दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। परियोजना के त्वरित क्रियान्वयन

हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल स्वीकृत धनराशि का 40 प्रतिशत, अर्थात 463.77 लाख (4.63 करोड़) की प्रथम किस्त भी जारी कर दी गई है। इससे निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

परियोजना पूर्ण होने पर शारदा नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में भू-कटाव पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा, लगभग 28 हेक्टेयर कृषि भूमि सुरक्षित होगी तथा चिलियाघोल क्षेत्र की आवासीय एवं स्थानीय परिसंपत्तियों को संरक्षण मिलेगा। इसके साथ ही बाढ़ से होने वाले नुकसान में उल्लेखनीय कमी आएगी और स्थानीय नागरिकों को सुरक्षित एवं स्थिर जीवन-पर्यावरण प्राप्त होगा। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि तटबंध निर्माण कार्य निर्धारित तकनीकी मानकों एवं उच्च गुणवत्ता के साथ समयबद्ध रूप से पूर्ण कराया जाएगा तथा कार्यों की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार संवेदनशील क्षेत्रों के लिए ठोस एवं स्थायी समाधान सुनिश्चित कर रही है।

इस परियोजना से टनकपुर एवं आसपास के क्षेत्रों को बाढ़ की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी और क्षेत्र के समग्र विकास को नई गति प्राप्त होगी।

मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत 3 करोड़ 2 लाख खातों में ट्रांसफर

संवाददाता

देहरादून। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत लाभार्थियों को 3 करोड़ 2 लाख रुपए से ज्यादा की धनराशि जारी की।

आज यहां महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत लाभार्थियों को 3 करोड़ 2 लाख रुपए से ज्यादा की धनराशि जारी की।

कैंप कार्यालय पर धनराशि लाभार्थियों की खातों में डीबीटी करने के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इस योजना में प्रदेश सरकार 2020 से ही कोरोना महामारी के समय अभिभावकों को खो देने वाले बेसहारा बच्चों को प्रति माह 3000 की सहायता राशि देती है। इस योजना के तहत जनवरी 2026 तक का धन पहले ही जारी कर दिया गया था।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि फरवरी में 5057 लाभार्थियों को कुल एक करोड़ 51 लाख 71 हजार रुपए आज जारी किए गए हैं। जबकि मार्च महीने के लिए कुल 5025 लाभार्थियों के 1 करोड़ 50 लाख 75 हजार रुपए की धनराशि जारी की गई है। इस योजना के तहत लाभार्थी के 21 वर्ष के हो जाने या बालिका लाभार्थियों के विवाह या लाभार्थी के सेवायोजित हो जाने के बाद वह योजना से बाहर हो जाते हैं।

इस अवसर पर सीपीओ अंजना गुप्ता और डिप्टी सीपीओ राजीव नयन आदि उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी के निर्देश पर लोहाघाट क्षेत्र में सघन स्वच्छता अभियान तेज

ग्रामीण अंचलों में सफाई व्यवस्था सुदृढ़

हमारे संवाददाता

चम्पावत। जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देशानुसार जिला पंचायत द्वारा लोहाघाट के विभिन्न ग्रामीण अंचलों में सघन स्वच्छता अभियान प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत दूरस्थ क्षेत्रों में भी विशेष स्वच्छता टीमों की तैनाती सुनिश्चित की गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा सके।

अपर मुख्य अधिकारी कमलेश सिंह बिष्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि तैनात स्वच्छता टीमें नालियों, संपर्क मार्गों एवं सार्वजनिक स्थलों की नियमित और व्यवस्थित सफाई कर रही हैं। साथ ही ग्रामीणों को कूड़ा प्रबंधन एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है, जिससे स्वच्छता को जनभागीदारी से जोड़ते हुए स्थायी बनाया जा सके। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि स्वच्छता को सामाजिक दायित्व के रूप में अपनाते हुए निरंतर जनजागरूकता बढ़ाई जाए। उन्होंने प्राकृतिक जल स्रोतों, गधेरों एवं पैदल मार्गों की नियमित सफाई सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया, जिससे जनपद में आने वाले आगंतुकों, पर्यटकों एवं स्थानीय नागरिकों को स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध हो सके।

उन्होंने जनपद के समस्त नागरिकों से अपील की है कि कूड़ा निर्धारित कूड़ेदानों में ही डालें तथा यदि किसी स्थान पर कूड़ेदान की आवश्यकता हो तो इसकी सूचना संबंधित अधिशासी अधिकारी, खंड विकास अधिकारी अथवा उपजिलाधिकारी को दें, ताकि समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

20 भिक्षुकों के खिलाफ भिक्षुक अधिनियम में मुकदमे दर्ज

हरिद्वार। आपरेशन लगाम के तहत बड़ी कार्यवाही करते हुए पुलिस ने 20 भिक्षुको के खिलाफ मुकदमें दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन लगाम को सुगम बनाने हेतु दिये गये दिशा निर्देश के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर हरिद्वार के कुशल नेत्तृव में आज कोतवाली नगर पुलिस द्वारा पुलिस टीमे गठित कर हर की पैडी क्षेत्र में घाटो पर आने जाने वाले यात्रियो से जबरदस्ती भीख मांगना एवं यात्रियों से बदसलूकी करने मे 20 भिखारियो के खिलाफ भिक्षुक अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमें दर्ज किये गये है। जिन पर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की जान बचाना पुण्य से कम नहीं: बत्रा

हमारे संवाददाता

हरिद्वार। परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा हीरो मोटो कोर्प के सीएसआर कार्यक्रम राइड सेफ इंडिया के अंतर्गत, उप क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (एआरटीओ), हरिद्वार के सहयोग से "सुरक्षित साथी-रोड सेफ्टी एवं इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रशिक्षण कार्यक्रम" का सफल आयोजन आज हरिद्वार स्थित एक स्थानीय होटल में किया गया। जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने दीप प्रज्वलित कर किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सभी वाहन चालकों को नियमों का पालन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अपनी जान से ज्यादा दूसरों को जान की सुरक्षा बहुत जरूरी है,इसके लिए यह जरूरी है कि सावधानी से वाहन चलाए,किसी भी दशा में वाहन तेज रफ्तार से न चलाए एवं वाहन चलाते समय किसी भी दशा में मोबाइल का प्रयोग न किया जाए, अधिकतर दुर्घटनाएं वाहन चलाते समय

मोबाइल पर बात करने से हो रही है । उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन पर बात न करने,ओवर स्पीड न हो एवं यातायात नियमों का पालन करने से ही सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि सभी दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट का उपयोग हर हाल में करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना में कोई व्यक्ति घायल होता है तो उसे तुरंत नजदीकी चिकित्सालय में पहुंचने में मदद करे,किसी व्यक्ति की जान बचाना किसी पुण्य से कम नहीं है।

उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल नियमों का पालन भर नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है। दुर्घटनाओं में 'गोल्डन ऑवर' के दौरान सही और त्वरित सहायता अनेक जीवन बचा सकती है।

इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम समाज में जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ एक जिम्मेदार और संवेदनशील यातायात संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।"

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी पी आर चौहान ने कहा कि जिस उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उसका सभी को नियमों का पालन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ओवर टेक एवं तेज रफ्तार के कारण ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हो रही है साथ ही उन्होंने कहा कि हैं सभी को यह शपथ लेनी चाहिए कि न ओवरटेक करेंगे,न तेज रफ्तार से वाहन चलाएंगे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि अपर जिलाधिकारी पी आर चौहान, संभागीय परिवहन अधिकारी डॉ. अनीता चमोला, संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी, सीओ ट्रैफिक बिपेंदर सिंह, प्लांट एच आर हेड पंकज भट्ट, प्लांट हेड सुनील कुमार मौजूद रहे।

विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भाजपा-कांग्रेस और यूकेडी सक्रिय

यूकेडी में युवाओं की फौज, भाजपा-कांग्रेस 'टेंशन' में

संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड का एकमात्र क्षेत्रीय राजनीतिक दल यूकेडी में युवाओं की फौज से भाजपा-कांग्रेस की 'टेंशन' बढ़ गई है। यूकेडीईआने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की 70 सीटों पर युवाओं की टीम के साथ मैदान में उतरेगा। यह दावा यूकेडी के यूथ ब्रिगेड का है। यूकेडी की घोषणा से भाजपा-कांग्रेस की राह आसान नहीं होगी।

बता दें कि यूकेडी राज्य बनने के बाद साल 2002 के विधानसभा चुनाव में चार, 2007 में तीन, 2022 के विध ानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में यूकेडी के 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा से भाजपा-कांग्रेस 'चिंतित' है। प्रदेश में लंबे समय से युवा विभिन्न समस्याओं से लेकर कई अन्य मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर सदन तक अपना गुस्सा जाहिर कर चुका है। इससे सरकार और भाजपा सहित कांग्रेस चिंतित है।

आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने सक्रियता तेज कर दी है। यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने बड़ा ऐलान किया कि पार्टी राज्य की सभी 70 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। उन्होंने कहा कि यूकेडी उत्तराखंड के मूल मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी और मजबूत विकल्प के रूप में उभरेगी।

यूकेडी के इस दावे के बाद राजनीतिक विशेषज्ञों की मानें तो आने वाले विध ानसभा चुनाव में अगर युवाओं ने एकजुटता दिखाई तो भाजपा-कांग्रेस की राह आसान नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि यूकेडी की

- **विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी में जुटा यूकेडी**
- **प्रदेश की 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया दावा**
- **एक बूथ, दस युवा नारे को दी जा रही चुनाव को धार**

यूथ ब्रिगेड़ लंबे समय से बीजेपी और कांग्रेस पर तीखे हमले बोल रही है। यहीं नहीं दोनों दलों पर प्रदेश का अहित करने का आरोप व राजधानी के मुद्दे पर सरकार और भाजपा-कांग्रेस पर तीखा पहार करने के साथ ही इन्हें उत्तराखंड के हितों के खिलाफ बता रही हैं। यूकेडी नेताओं का आरोप है कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण जिन सपनों और उद्देश्यों के साथ हुआ था बीजेपी और कांग्रेस ने बारी-बारी से सत्ता में आकर उन सपनों को तोड़ने का काम किया है।

आगामी विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी यूकेडी आमजन के बीच जा रही है। पहाड़ के युवा और महिलाएं पार्टी को नई दिशा देने का काम कर रही हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो यूकेडी 'एक बूथ, दस युवा' के नारे के साथ संगठन को मजबूत कर रही है। युवाओं और महिलाओं को संगठन से जोड़ने का अभियान तेज किया गया है।

आने वाले विधानसभा चुनाव में यूकेडी के अभी के प्रदर्शन को लेकर भाजपा-कांग्रेस अभी से 'टेंशन' में आ गई है। इसके लिए दोनों दल अपनी-अपनी रणनीति तय करने में लगी है ताकी चुनाव में इसका फायदा मिल सके।

इन मुद्दों को लेकर घेर रहे भाजपा-कांग्रेस को

यूकेडी के युवा नेताओं की माने तो भाजपा-कांग्रेस ने प्रदेश के जल, जंगल और जमीन को माफियाओं के हवाले कर दिया गया है, जबकि, आम जनता आज भी मूल निवास, सशक्त भू-कानून और गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाए जाने जैसे मुद्दों पर न्याय की प्रतीक्षा कर रही है।

राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पलायन जैसे मूलभूत मुद्दों पर सरकारें पूरी तरह विफल साबित हुई हैं। पहाड़ से लगातार हो रहे पलायन ने गांवों को खाली कर दिया है, लेकिन सरकार के पास इसे रोकने के लिए कोई ठोस नीति नहीं है।

चार साल की उपलब्धियों के नाम पर जनता को भ्रमित कर रही सरकार: धस्माना

संवाददाता

देहरादून। कांग्रेस प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि चार साल की उपलब्धियों के नाम पर प्रदेश की जनता को सरकार भ्रमित कर रही है।

आज यहां प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने उत्तराखंड में भाजपा की धामी सरकार के चार साल पूरे होने पर मनाए गए जश्न और सरकार के दावों को झूठ का पुलिंदा बताते हुए कहा कि अगर सरकार के दावे सही हैं और सरकार में नैतिक साहस है तो वो पिछले चार साल में प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने वाले युवाओं, राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की सेहत, प्रदेश की प्राइमरी माध्यमिक व उच्च शिक्षा में हुई प्रगति व वित्तीय प्रबंधन , राज्य पर कर्ज और देनदारियों के विवरण विषयों पर एक अधिकारिक श्वेत पत्र जारी कर प्रदेश की जनता को वस्तु स्थिति से अवगत करवाए। कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए

धस्माना ने कहा कि सरकारी दावों की हकीकत यह है कि प्रदेश में बेरोजगारी पिछले पच्चीस वर्षों में अपने चरम पर है। उन्होंने कहा कि पिछले आठ वर्षों में प्रदेश में केवल एक बार पुलिस भर्ती हुई जबकि प्रदेश में सिपाही,हैड कांस्टेबल व कांस्टेबल के हजारों पद खाली पड़े हैं और थाने चौकियां में फोर्स का आवंटन तीस से चालीस प्रतिशत कम है जबकि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है और ट्रैफिक सिस्टम भी चरमराया हुआ है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार शिक्षा विभाग में प्राइमरी से लेकर माध्यमिक स्कूलों में हेड मास्टर व प्रधानाध्यापक के हजारों पद व उच्च शिक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर के सैकड़ों पद रिक्त पड़े हैं। धस्माना ने कहा कि इसी प्रकार राज्य के अनेक सरकारी महकमों में कर्मचारियों के पद रिक्त पड़े हैं। धस्माना ने कहा कि प्रदेश की सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है और प्रदेश के जिलों की सीएचसी पीएचसी की बात तो दूर जिला अस्पतालों में विशेषज्ञ डाक्टर नहीं हैं और वो केवल रेफरल केंद्र बने हुए हैं। धस्माना ने कहा कि हालात इतने खराब हैं कि प्रदेश की सरकार हरिद्वार का सरकारी मेडिकल कालेज नहीं चला पाई और उसे पीपीपी मोड में दे दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वित्तीय प्रबंधन भी पटरी से उतरा हुआ है और राज्य में बजट के आकार के बराबर ऋण चढ़ गया है और प्रदेश सरकार उधार का घी खा कर तालियां बजा रही है। कानून व्यवस्था के मामले में धस्माना ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उत्तराखंड देश के हिमालयी राज्यों में पहले पायदान पर आ गया और अंकिता भंडारी से लेकर संतरेसा हरिद्वार में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या जैसे अपराधों में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और दायित्व धारी शामिल रहे। धस्माना ने कहा कि चार साल में प्रदेश को जिस बदहाली की स्थित में भाजपा सरकार ने पहुंचा दिया उस पर अब जनता सरकार से जवाब चाहती है।

अग्निकांड: 5 से 6 आवासीय मकान आग की चपेट में, रेस्क्यू जारी

हमारे संवाददाता

उत्तरकाशी। मोरी तहसील के अंतर्गत फिताडी गांव में कल देर रात आवासीय भवनों में भीषण आग लग गई आग इतनी ज्यादा थी कि देखते ही देखते आग 5 से 6 मकानों में फैल गई और गांव में भीषण अग्निकांड से लोगों की चीख पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि आग लगने की घटना की सूचना ग्राम प्रधान फिताडी द्वारा आपदा प्रबंधन को दूरभाष से दी गई। आग लगाने की सूचना

मिलते ही मौके के लिए कल रात्रि को पुलिस, एसडीआरएफ, फायर सर्विस ,राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम मौके पर रवाना हुई । ग्राम प्रधान एवं एसडीआरएफ टीम के कार्मिकों के द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम फिताडी में 5 से 6 आवासीय भवनो में अभी भी आग लगी हुई है। घटनास्थल पर एस.डी.आर.एफ. एवं पुलिस की टीम तथा स्थानीय ग्रामीणों द्वारा आग बुझाने का कार्य किया जा रहा है। अभी तक किसी प्रकार की जनहानि एवं पशु हानि होने की सूचना नही है।

स्मैक के साथ महिला गिरफ्तार

देहरादून। पुलिस ने स्मैक के साथ महिला को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसको न्यायालय में पेश किया जहां से उसको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार विकासनगर कोतवाली पुलिस ने कसाई मौहल्ला के पास एक महिला को संदिग्ध अवस्था में घुमते हुए देखा तो उसको रूकने का इशारा किया। पुलिस को देख वह भाग खडी हुई। पुलिस ने पीछा कर उसको थोडी दूरी पर ही पकड लिया। तलाशी लेने पर पुलिस ने उसके कब्जे से 14.58 ग्राम स्मैक बरामद कर ली। पूछताछ में उसने अपना नाम रूखसाना पत्नी मौहम्मद सलीम निवासी कुन्जाग्रान्ट बताया। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसको न्यायालय में पेश किया जहां से उसको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

मकान का ताला तोड नगदी व जेवरात चोरी

संवाददाता

देहरादून। चोरों ने मकान का ताला तोड वहां से जेवरात व नगदी चोरी कर ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार ठाकुर पुर निवासी अनिशा रावत ने रायवाला थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि वह परिवार के साथ बाहर गयी थी। आज जब वह वापस आयी तो उसने देखा कि उसके मकान का ताला टूटा हुआ था। अन्दर अलमारी का ताला तोडकर चोरों ने नगदी व जेवरात चोरी कर लिये। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

जुआ खेलते छह गिरफ्तार

देहरादून(संवाददाता)। पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार डोईवाला कोतवाली पुलिस ने लालतप्पड के पास एक स्थान पर छापा मारा तो वहां से छह लोगों को ताश के पत्तों से हारजीत की बाजी लगाते गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उन्होंने अपने नाम इकबाल पुत्र इरफान निवासी ज्वालापुर हरिद्वार, नरेश पुत्र अमरजीत निवासी लालतप्पड डोईवाला, देवेन्द्र सिंह पुत्र ज्ञानचन्द निवासी लालतप्पड, विमल पुत्र ज्ञान सिंह निवासी शेरगढ लालतप्पड, सुनिल पुत्र ब्रहमानंद निवासी नूनावाला, संदीप सिंह निवासी शेरगढ लालतप्पड डोईवाला बताया। पुलिस ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

शराब के साथ दो गिरफ्तार

देहरादून। पुलिस ने शराब के साथ दो लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार डोईवाला कोतवाली पुलिस ने ऋषिकेश रोड पर एक ऑटो चालक को रूकने का इशारा किया तो पुलिस को देख वह ऑटो को तेजी से भगा ले गया। पुलिस ने पीछा कर उसको थोडी दूरी पर ही दबोच लिया। तलाशी लेने पर पुलिस ने ऑटो से चार पेटी शराब की बरामद कर ली। पूछताछ में उसने अपना नाम श्यामू पुत्र भुवनेश्वर निवासी कल्याण आश्रम पटेलनगर बताया। वहीं पटेलनगर कोतवाली पुलिस ने विशाल मेगामार्ट के पीछे से एक को 52 पव्वे शराब के साथ गिरफ्तार किया जिसने अपना नाम रविन्द्र साहनी पुत्र रामनिवास निवासी लोहिया नगर बताया।पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर वाहन को सीज कर दिया।

आर.एन.आई.- 59626/94

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक श्रीमती पुष्पा कांति कुमार द्वारा दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग घंटाघर, देहरादून से प्रकाशित तथा अवि प्रिंटर्स 21 ईसी रोड, देहरादून से मुद्रित।

प्रधान संपादक
कांति कुमार

संपादक
पुष्पा कांति कुमार

समाचार संपादक
आनंद कांति कुमार

कानूनी सलाहकार:
वी के अरोड़ा, *एडवोकेट*
बैजनाथ, *एडवोकेट*

कार्यालय: दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग देहरादून।
मो. 9358134808

नोट: सभी विवादों के लिये देहरादून न्यायालयहीमान्यहोगा.प्रकाशितसामग्रीके लिए प्रिंटर्स की कोई जिम्मेदारी नहींहोगी।